tuted any committee to set up and encourage industries in the tribal areas of Gujarat State;

(b) if so, the steps taken by Government to bring industrial revolution in the tribal and rural areas of this region and to provide opportunities of self-employment to the unemployed youth there; and

(c) the funds proposed to be allocated for this purpose by Government in the next financial year, 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) No, Sir.

(b) The Khadi & Village Industries Commission has taken number of steps to improve the production and thereby employment in Khadi & Village Industries in Gujarat. KVIC has a proposal to implement Special Employment programme in 125 Blocks in the country. Under this programme the following blocks have been selected in Gujarat. The employment generation in each block is expected to be 1000.

| *Districts* | *Blocks* |
|---|---|
| 1. Valsad | Darampur |
| 2. Surat | Palsana |
| 3. Rajkot | Jasdan |
| 4. Sabarkantha | Meghraj |
| 5. Bhavnagar | Savarkundla |
| 6. Surendranagar | Desada. |

Besides the above, as per recommendation of the High Power Committee, KVIC has also decided to implement Special Programme in 50 backward districts of the country. In Gujarat, the Special Employment Programme is implemented in Banaskantha and Panchmahal districts. The employment generation in each district under this programme is estimated to be 1000 persons.

(c) KVIC is yet to earmark funds for these activities for 1995-96 for Gujarat.

**लघु उद्योगों में निवेश की सीमा में वृद्धि**

4781. **श्री राम जेठमलानी:**
**श्रीमती सुषमा स्वराज:**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश के लघु उद्योगों में पूंजी निवेश की सीमा 1.5 करोड़ रुपये करने तथा बड़े और मध्यम उद्योगों की लघु उद्योगों में भागीदारी 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत तक करने के निर्णय से लघु उद्योग की इकाइयों पर होने वाले प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि लघु उद्योगों में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था श्रम प्रधान होने के कारण तुलनात्मक दृष्टि से रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा लघु उद्योगों मे पूंजी प्रधान व्यवस्था स्थापित होने से कौन से अतिरिक्त लाभ होने की सम्भावना है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) निवेश और लघु उद्योगों में इक्विटी भागीदारी की अधिकतम सीमा बढ़ाने के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किन्तु ऐसे मामलों में कोई निर्णय लेने से पहले सभी सम्बद्ध बातों पर विचार किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) जी, हां।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**लघु उद्योग एककों में उत्पादन और निर्यात**

4782. **श्री राम जेठमलानी:**
**श्रीमती सुषमा स्वराज:**

क्या प्रधान मंत्री 16 मार्च, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 680 के दिए गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि लघु उद्योग देश के कुल, उत्पादन में 40 प्रतिशत का योगदान करते हैं तथा देश के कुल निर्यात में 35 प्रतिशत योगदान इनका होता है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं; और